जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर
Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 138 प्रभात उदयपुर, रविवार 23 मार्च, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ट्रंप की आशा के विपरीत, यूक्रेन-रूस युद्ध और सघन व खतरनाक हुआ

यूक्रेन ने रूस के भीतरी भागों में जबरदस्त ड्रोन-एटैक किया और बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुँचाया तथा गिरते हुए मलबे से काफी अफरा-तफरी मची रूस के शहर में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने के डॉनल्ड ट्रंप के वादे के विपरीत, अब यूक्रेन में लड़ाई और अधिक भयंकर हो गई है और यूक्रेन ने भी रूस में काफी अंदर तक जाकर भारी ड्रोन हमले किए हैं।

ट्रंप का प्रस्ताव था कि कम से कम एक माह के लिए सीमित युद्ध विराम हो, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा संयंत्रों) को निशाना नहीं बनाएं। इसके विपरीत, रूस और यूक्रेन दोनों ने प्रतिशोध की नई और तीव्र भावना के साथ ऊर्जा केन्द्रों पर हमले किए हैं।

यूक्रेन ने रूस के भीतरी भागों में जबरदस्त ड्रोन हमले किए हैं, जिसने रूसियों को चकित कर दिया है। जवाबी कार्यवाही में रूस ने यूक्रेन के कुछ ऊर्जा संयंत्रों के साथ-साथ शहरों और नागरिक ठिकानों पर विनाशकारी हमले किए हैं।

यूक्रेनी हमलों के जवाब में रूसी सेना ने सुमी और डोनेटस्क क्षेत्र में वोल्गो रोड क्षेत्र जैसे कुछ क्षेत्रों पर भारी हमले किए है। वहीं, यूक्रेन के कुछ ड्रोन हमलों की वजह से रूस में इमारतों को काफी नुकसान हुआ है और चारों और गिरते हुए

- दूसरी ओर रूस ने बदले की भावना से यूक्रेन पर धावा बोला। कुर्स्क क्षेत्र में, जहाँ यूक्रेन ने रूस की काफी भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, वहाँ से, रूस की भारी गोलाबारी के दबाव में, यूक्रेन को लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र छोड़कर पीछे हटना पड़ा।
- ट्रंप ने यूक्रेन व रूस के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि 30 दिन का युद्ध विराम रहेगा तथा इस अवधि में दोनों देश एक दूसरे के बिजली संयंत्र आदि पर गोलाबारी नहीं करेंगे। पर, युद्ध विराम का प्रस्ताव, अस्वीकार सा ही रहा तथा दोनों देशों ने एक दूसरे के बिजली संयंत्रों आदि पर जमकर बमबारी की।
- रूस का हमला इतना भयंकर था, बिजली के संयंत्रों व नागरिक प्रतिष्ठानों पर कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ैलैंस्की, सीमा का दौरा करने को बाध्य हुए, सेना का मनोबल ऊंचा रखने के लिए।

मलबे ने जनता में व्यापक रूप से सार्वजनिक भय पैदा कर दिया है।

ट्रंप के सीमित युद्ध विराम प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए, रूसियों ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे और नागरिक लक्ष्यों पर नए उन्माद के साथ फिर से हमले शुरु कर दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्पति को अपनी सेना के मनोबल को बनाए रखने के लिए वर्तमान में फ्रंटलाइन पर जाना पड़ा है, जहाँ यूक्रेनी सेना भारी दबाव में है।

रूस के कुर्स्क क्षेत्र में, जहाँ यूक्रेन ने रूस की बड़ी ज़मीनों पर कब्जा किया था, रूस ने पलटवार हमले शुरु किए हैं और यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। रूस ने हाल ही में दावा किया है कि उसने 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया है, जो पहले यूक्रेनी नियंत्रण में था।

इस नुकसान के कारण, सऊदी अरब के नेतृत्व वाली वार्ता में यूक्रेन की सौदेबाजी की स्थिति कमज़ोर हो गई है। वार्ता करने वाले अमेरिकी और यूक्रेनी दल इन रूसी क्षेत्रों को रूसियों के साथ सौदेबाजी के कार्ड के रूप में देख रहे थे। अब, यूक्रेनी पक्ष अपनी सौदेबाजी की ताकत को तेजी से खोता जा रहा है।

यह संभव है कि रूसियों ने डॉनल्ड ट्रंप और अमेरिकी दबाव को चुनौती देने के लिए कुछ सोच-समझ कर कदम उठाए हों। यह स्पष्ट है कि अमेरिका विभिन्न मोर्चों पर विभिन्न समूहों और ताकतों के दबाव में हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध वार्ता से अलग हो रहा है, क्योंकि वो अन्य हमलों और गतिविधियों के कारण स्वयं दबाव में है। लाल सागर क्षेत्र में हूती विद्रोहियों ने अलग-अलग फैले ठिकानों से अमरीकियों और इज़रायल पर गंभीर हमला किया है। हूतियों ने अमेरिकी नौसेना के "हैरी एस. ट्रूमैन" विमानवाहक पोत पर मिसाइलों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो अति.मु.सचिवों को सिविल कारावास

जयपुर, 22 मार्च। शहर के वाणिज्यिक न्यायालय क्रम-1 ने अवॉर्ड राशि का भुगतान नहीं करने के दो अलग-अलग मामलों में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता और भास्कर ए सावंत को तीन-तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी

- वाणिज्यिक न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत को दो अलग-अलग मामलों में तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर ठेकेदारों को निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने का आरोप है।

गई है, जिस पर अदालत अगले सप्ताह सुनवाई करेगी।

जयपुर के वाणिज्यिक न्यायालय क्रम-1 ने ठेकेदारों को भुगतान नहीं होने से संबंधित विवाद पर अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर यह आदेश दिए। नागौर मुकुंदगढ हाईवे प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2020-21 में सड़क का निर्माण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पिछले वर्ष ओडिशा चुनाव से पूर्व तत्कालीन मु.मंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य के बारे में कई चर्चाएं शुरु हुई थीं

कुछ ऐसा ही क्रम अब बिहार में चल रहा है और भारी अटकलबाजियाँ चल रही हैं मु.मंत्री नीतीश कुमार की मानसिक व शारीरिक "हैल्थ" के बारे में

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। गत वर्ष ओडीशा विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से विवाद पैदा हुए थे, बिल्कुल उसी तरह बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के "मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य" को लेकर एक अभियान जोर पकड़ रहा है।

राज्य में विधानसभा चुनाव इस वर्ष अक्टूबर -नवम्बर में होने हैं, ऐसे में नीतीश कुमार की मानसिक- शारीरिक स्थिरता को लेकर पैदा हो रहे विवाद एन.डी.ए. गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा के नज़दीक माने जाने वाले न्यूज़ चैनल, नीतीश के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न उठाते हुए कई कार्यक्रम प्रसारित कर चुके हैं। इन घटनाक्रमों से इन संदेहों को बल मिल रहा है कि नवम्बर में होने वाले चुनावों में भाजपा अकेले ही उतरेगी। पर इन विवादों के लिए खुद नीतीश ही जिम्मेवार हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक क्लिप में प्रधान सचिव दीपक कुमार के साथ बातें करते व ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं जबकि उस समय राष्ट्रगान बज रहा था। यह

- मजे की बात यह भी है कि चर्चाओं का यह अभियान उन चैनलों पर ज्यादा जोर-शोर से चल रहा है, जो भाजपा के नज़दीक माने जाते हैं।
- इससे जनता यह कयास लगाने लगी है कि कहीं भाजपा, नीतीश से संबंध-विच्छेद करके अकेले ही चुनाव तो नहीं लड़ना चाहती, अक्टूबर-नवम्बर में प्रस्तावित असैम्बली इलैक्शन में।
- शायद इन अटकलबाजियों के लिये स्वयं नीतीश ही जिम्मेवार हैं।
- हाल ही में उनका सार्वजनिक आचरण कुछ अटपटा जरूर रहा है। पटना में आयोजित एक अंतरर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के बाद, "जन-गण-मन..." के गायन के समय वे अपने सचिव व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के साथ हंसते हुए, बतियाते हुए सभी चैनल्स पर दिखे।
- इसी प्रकार, महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस, जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर, श्रद्धांजलि देने के बाद नीतीश कुमार, ताली बजाते दिखे थे। इसके अलावा वे आजकल यदा-कदा सार्वजनिक समारोह में, लोगों के, विशेषकर प्र.मंत्रीमोदी के पैर छूते हुए भी नज़र आ जाते हैं टी.वी. पर।

घटना पटना में आयोजित इंटरनैशनल स्पोर्ट्स कार्यक्रम की है। इससे पहले जनवरी में भी कुमार ने एक विवाद खड़ा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

6 राज्यों के मुख्यमंत्री व प्रांतीय नेता एकत्रित हुए स्टालिन के निमंत्रण पर

इनका घोषित उद्देश्य था भारतीय गणतंत्र और संघीय ढांचे को बचाना

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। आंध्र प्रदेश को छोड़कर समूचा दक्षिण भारत शनिवार को चेन्नई में एकत्रित हुआ और "परिसीमन" कवायद, जिसे इन्होंने अनुचित व अन्यायपूर्ण करार दिया है, के खिलाफ विरोध जताया। इनका मत है कि परिसीमन से संसद में दक्षिण का प्रतिनिधित्व और महत्व कम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में सत्तारुढ़ पार्टी तेलुगूदेशम और विपक्षी पार्टी वायएसआरसीपी दोनों ही भाजपा की गोद में बैठी हैं।

तकनीकी रुप से देखें तो परिसीमन के खिलाफ पहली जॉइन्ट एक्शन मीटिंग का विस्तार पूर्व और उत्तर तक हुआ, साथ ही इसमें ओडिशा से बीजू जनता दल और पंजाब से आम आदमी पार्टी ने भी शिरकत की। मीटिंग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने बुलाई थी। इस विचार की सफलता और इसके क्रियान्वयन ने स्टालिन को राज्य

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने जॉइन्ट एक्शन कमेटी मीटिंग को भारतीय गणतंत्र व संघवाद की रक्षा के लिए ऐतिहासिक दिन बताया।

से बाहर भी बतौर नेता स्थापित कर दिया है।

भाजपा की स्थानीय इकाई ने मीटिंग स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और काले झंडे लहराए। उन्होंने स्टालिन व उनके सहयोगियों पर कावेरी और मुलाई पेरियार मुद्दे पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने केरल के आगे घुटने टेक दिए हैं, जिसने तमिलनाडु को मैडिकल कचरे का डंपयार्ड बना दिया है और अपनी कमियां छुपाने के लिए वे व्यर्थ का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी हार तय है।

इसमें रोचक बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने अपने दो प्रतिनिधि मीटिंग में भेजे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रैवन्त रेड्डी ने बैठक में भाग लिया। कांग्रेस जानती है कि उत्तर भारत से उसे ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां भाजपा का दबदबा है। यूपी में कांग्रेस पूरी तरह से सपा पर आश्रित है।

स्टालिन ने परिसीमन पर जॉइन्ट एक्शन कमेटी मीटिंग को भारत के संघीय ढांचे की सुरक्षा की दिशा में एतिहासिक दिवस बताया वहीं अन्य सभी दलों ने लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन की निंदा की।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस.आई. पेपर लीक मास्टरमाइंड की साली फरार

जयपुर, 22 मार्च । प्रदेश में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पोरव कालेर की साली प्रियंका गोस्वामी फरार हो गई है। प्रियंका गोस्वामी जैसलमेर पुलिस लाइन में तैनात थी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 18 मार्च को महिला ट्रेनी एसआई प्रियंका गोस्वामी को पूछताछ के लिए आदेश

- गहलोत सरकार के कार्यकाल में सबसे चर्चित पेपरलीक मामले की जांच जोर पकड़ रही है और जांच कर रही एसआईटी ने 15 से 20 ट्रेनी एसआई को शक के दायरे में लिया है।

जारी किया था। लेकिन 21 मार्च को वह गायब हो गई।

एसओजी एडीजी वीके सिंह ने बताया कि जब मास्टरमाइंड पोरव कालेर से पूछताछ की गई, तो यह जानकारी सामने आई कि करीब 15 से 20 ट्रेनी एसआई को पेपर पढ़ाया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य छीने

सुप्रीम कोर्ट ने जाँच के लिए तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों का पैनल बनाया है

नई दिल्ली, 22 मार्च। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी कैश मिलने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कार्य से सस्पैंड कर दिया है। जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। न्यायपालिका का पक्ष सबके सामने रखने के लिए सीजेआई संजीव खन्ना ने सारा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सब रिकॉर्ड पब्लिक होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने 21 मार्च को इंटरनल इन्क्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना को सौंपी थी। शनिवार शाम सीजेआई ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए

- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए मामले का सारा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है।
- इसी के तहत दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय की रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा का जवाब, जाँच समिति की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
- ज्ञातव्य है कि गत 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगने के दौरान कथित तौर पर भारी मात्रा में कैश मिला था, इसको लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म है।

तीन सदस्यीय समिति बनाई और दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक काम न सौंपने को कहा है।

सीजेआई संजीव खन्ना ने बड़ा कदम उठाया है। अब इस मामले से जुड़ी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा का जवाब और अन्य दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं।

सीजेआई संजीव खन्ना ने आरोपों की जांच के लिए जो तीन सदस्यीय समिति गठित की है, उसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। 21 मार्च को कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली के बंगले पर 14 मार्च की रात आग लगने के बाद कैश बरामद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)